ठीहा छत्तीसगढ़

समस्या से समाधान तक

हमारे **ई-पेपर** को पढ़ने के लिए इस **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे दैनिक खबरों को **डिजिटल माध्यम** में देखने के लिए इस **QR कोड को स्कैन करें**

वर्ष-01 | अंक-03 | पाक्षिक | 1 से 15 सितम्बर 2026 | मूल्य : 20 | पृष्ठ- 12

झीरम घाटी हमला: एनआईए कोर्ट ने 10 आरोपियों को दिया दोषी करार

कांग्रेस का दावा- न्याय अभी अधूरा, सियासी घमासान तेज

• **राकेश निर्मलकर,** संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले में 13 साल बाद जगदलपुर की विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। 25 मई 2013 को हुए इस नरसंहार में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत 32 लोगों की शहादत हुई थी। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इसे 'अधूरा न्याय' बताते हुए इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश होने का आरोप लगाया है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी तीखा पलटवार किया है।

स्पेशल जज अभय सिंह राजपूत की अदालत में 13 वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान 100 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस मामले में जिन 10 आरोपियों प्रमिला मोडियम, चैतू लेखन उर्फ मुन्ना, सुमित्रा उर्फ सुमित्रा पूनम मोडियम, मुक्का मांडवी, कोसा कवासी उर्फ कोसाराम, आयाता मरकाम, मढ़कामी देवा, जोगा मदकामी, बनजामी सन्ना और महादेव नाग को दोषी करार दिया गया है, सभी दोषियों को 16 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।

विपक्ष असंतुष्ट

यह एक बड़ी राजनीतिक साजिश, न्याय अधूरा है" कांग्रेस नेताओं ने एनआईए की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और घटना के 'षड्यंत्र वाले हिस्से' की जांच की मांग उठाई है।

भूपेश बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री): एनआईए की जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "विष्णु देव साय से मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी गठन करके जांच करना था, क्यों नहीं किया? क्यों डीजी से पूछताछ नहीं हुई? रमन सिंह से कब पूछताछ की गई?" उन्होंने इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश करार दिया।

दीपक बैज (प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष): सच्चाई उजागर करने के लिए उन्होंने नारको टेस्ट की मांग की: "अब एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता है नारको। तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी (नक्सल ऑपरेशन) का नारको टेस्ट होना चाहिए।"

उमेश पटेल (शहीद नंदकुमार पटेल के बेटे): "एनआईए ने अपनी चार्जशीट प्रस्तुत कर दी थी और उसका आज अंतिम फैसला है। उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन कास्परेसी पार्ट (साजिश) जिसके लिए हम लोग काफी समय से लगे हुए थे, उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे।"

छवेंद्र कर्मा (शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे): सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "जब हमारे पास कुख्यात नक्सली लीडर्स के द्वारा सरेंडर किया जाता है, उसके बावजूद जांच में कहीं किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं होता है। इसका सीधा-सीधा मतलब यही है कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है।"

टी.एस. सिंहदेव(पूर्व उपमुख्यमंत्री): सुरक्षा में हुई चूक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, "तीसरे दिन जब हम सुकमा की तरफ जा रहे थे तो एक भी पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल रास्ते में कहीं नहीं मिले। यह क्यों और यह कैसे? आपने जो मौका दिया वहां पर इस घटना को अंजाम देने के लिए..."

सत्ता पक्ष का पलटवार

जेब में सबूत लेकर घूमने वाले, एनआईए को क्यों नहीं देते?" कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर इस मुद्दे पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया है।

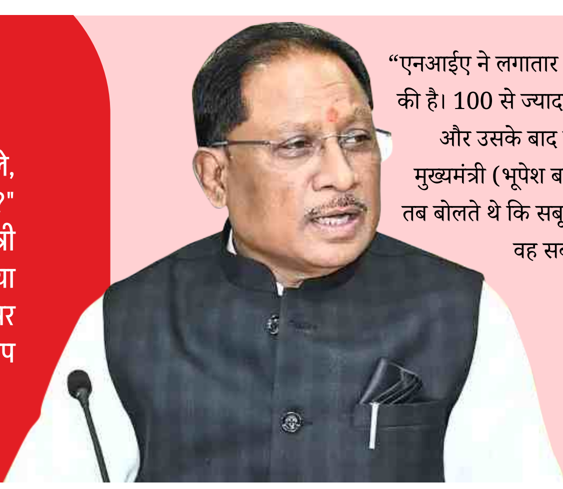

"एनआईए ने लगातार 13 वर्षों तक इसमें सुनवाई की है। 100 से ज्यादा गवाहो से गवाही ली गई है और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) तो जब विपक्ष में थे, तब बोलते थे कि सबूत जेब में लेकर घूमते हैं, तो वह सबूत एनआईए को देना था।"

~ सीएम
विष्णु देव साय

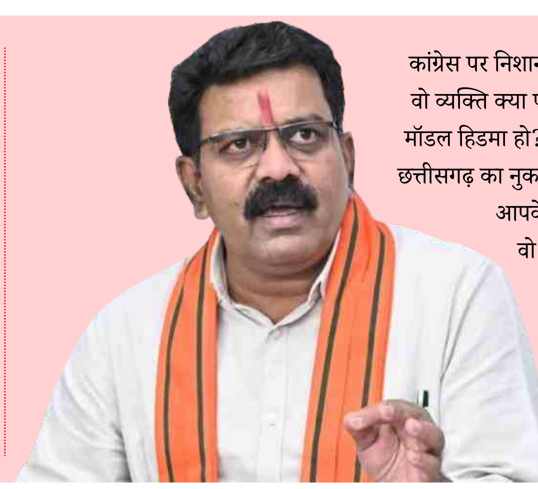

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "मुझे बताएं वो व्यक्ति क्या पूछ सकते हैं मुझसे, जिनके रोल मॉडल हिडमा हो? मुझे तो यह लगता है कि इसमें छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ है। मुझे बताओ आप, आपके जेब में जो झीरम का प्रमाण है वो देकर आओ ना एनआईए को।"

विजय शर्मा
(उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री)

हसदेव की हवा बदल गई है

या बदल गई है कहानी सुनाने की नीयत ?

• देवानंद, संपादक

किसी विज्ञापन को देखकर मुस्कुराना आसान है, पर उसे ध्यान से पढ़ना और भी ज़रूरी हो जाता है - खासकर तब, जब वह विज्ञापन किसी प्रदेश की पहचान, उसके संघर्ष और उसकी उपलब्धियों को अपनी कहानी बनाकर पेश करने लगे।

हाल ही में सामने आया एक विज्ञापन सेट चर्चा में है, जिसमें हसदेव क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के साथ लिखा गया है - "तरक्की की ओर बढ़ रही है, हसदेव की हवा बदल गई है।" पढ़ने में यह वाक्य सुंदर लगता है, प्रेरणादायक भी। पर सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच किसी एक कंपनी के CSR कार्यक्रम की वजह से किसी पूरे इलाके की "हवा" बदल जाती है? या फिर यह उस मेहनत, उस संघर्ष और उस सामूहिक विकास-यात्रा को छोटा करके दिखाने की कोशिश है, जो दशकों से इस प्रदेश के लोगों ने खुद अपने बलबूते तय की है?

छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जिसने अपनी अलग पहचान अपने परिश्रम, अपने संसाधनों और अपने नेतृत्व की सूझबूझ से बनाई है - चाहे वह किसी भी दल की सरकार रही हो। स्कूल खुले, सड़कें बनीं, अस्पताल पहुंचे, बिजली गांव-गांव तक गई - यह सब किसी एक विज्ञापन अभियान की देन नहीं, बल्कि वर्षों की नीतियों, प्रशासनिक प्रयासों और जनता के धैर्य का परिणाम है। ऐसे में जब कोई कॉर्पोरेट विज्ञापन इन उपलब्धियों को अपने कुछ पोस्टरों में समेटकर "हमने बदल दी हवा" कहने लगे, तो यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं, बल्कि एक पूरे प्रदेश के आत्मसम्मान से जुड़ा विषय बन जाता है।

यही वह बिंदु है जहां आम जनता, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारशील नागरिक सवाल उठा रहे हैं - क्या किसी कंपनी को इस प्रदेश की धरती, यहां के संसाधनों और यहां के लोगों से जो कुछ मिला है, उसका हिसाब भी कभी सामने आना चाहिए? विकास की कहानी हमेशा दोतरफा होती है - जो देता है, वह भी बदले में बहुत कुछ पाता है। ऐसे में सिर्फ एक पक्ष की तस्वीर दिखाकर पूरी तस्वीर बदल देने की कोशिश, जनमानस को सहज स्वीकार नहीं होती।

इसी बहस के बीच एक और आवाज़ उठती है, जो हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक गहरी चिंता जताती है - कल अगर यही विज्ञापन शैली बस्तर या प्रदेश के अन्य आदिवासी अंचलों पर लागू हो, तो कहीं ऐसा न हो कि वहां के परिश्रम, संस्कृति और गरिमा को भी इसी तरह सरल और सतही जुमलों में समेट दिया जाए। किसी समाज के जीवन-स्तर में आया बदलाव उसकी अपनी मेहनत, शिक्षा और अवसरों की कहानी होता है, न कि किसी विज्ञापन एजेंसी की सृजनात्मकता का प्रमाणपत्र। जब यह भेद मिट जाता है, तब विकास की बात करते-करते वह भाषा कहीं न कहीं उपहास जैसी लगने लगती है - भले ही नीयत ऐसी न हो।

यह लेख किसी सरकार, किसी दल या किसी नेतृत्व के विरुद्ध नहीं है - न सत्तापक्ष के, न विपक्ष के। यह सिर्फ इतना कहना चाहता है कि छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध और संघर्षशील प्रदेश की विकास - गाथा किसी एक विज्ञापन अभियान की मोहताज नहीं है। यहां की हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि और हर आम नागरिक ने अपने-अपने स्तर पर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। ऐसे में जब कोई निजी संस्थान अपने CSR कार्यों को प्रदेश के समूचे कायाकल्प के रूप में प्रस्तुत करने लगे, तो यह उन तमाम हाथों की मेहनत के प्रति असंतुलित नज़रिया बन जाता है, जिन्होंने असल में यह बदलाव लाया।

श्रेय लेने में कोई बुराई नहीं, पर श्रेय की सीमा भी होनी चाहिए। विकास की असली कहानी सुनाने का हक प्रदेश की जनता और उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों का है - किसी विज्ञापन बोर्ड का नहीं।

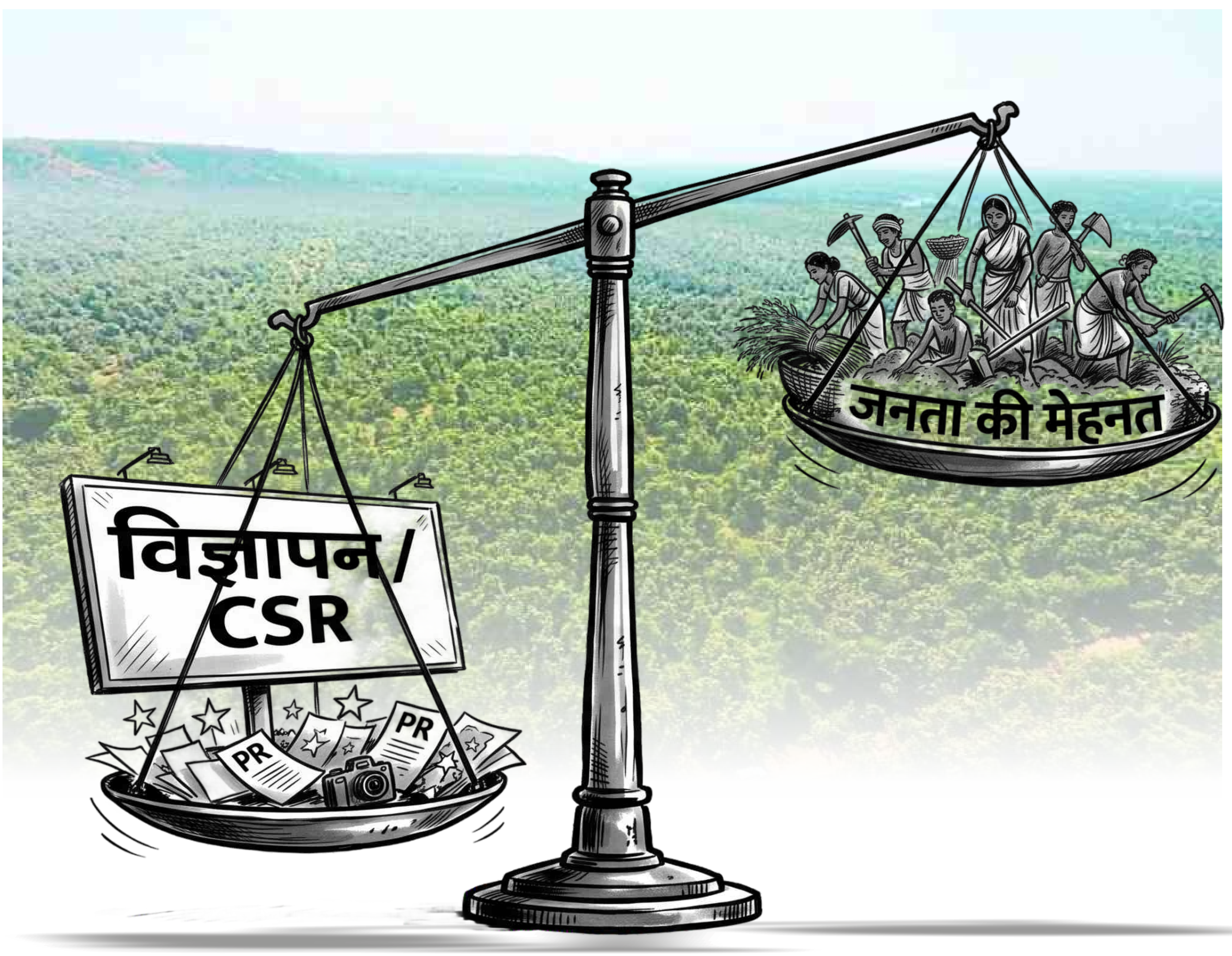

Printed by Published by **DEVANAND** on behalf of **DEVANAND**, printed at A.R. Printers, B-1, in front of raymond showroom, shivam market, pandri and published at 875, in front of mahaveer cutpiece, Baijnathpara, Raipur. ZIP - 492001. Editor- **DEVANAND**, Mobile No. - 99269 33309.

KBC-18 में ₹50 लाख जीतने वाले तेहका के योगेश साहू से विशेष बातचीत

IIT बॉम्बे से UPSC और करोड़पति के मंच तक का सफर

प्रश्न: योगेश जी, आपका केबीसी (KBC) तक पहुँचने का यह सफर कैसे मुमकिन हुआ?

योगेश साहू: मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत और भगवान की कृपा मानता हूँ। दरअसल, मेरी कोचिंग में एक भैया आए थे जो केबीसी में जा चुके थे, उन्हें देखकर मैंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया और किस्मत से पहली बार में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके बाद घर बैठे मोबाइल से दो चरणों को पास करने के बाद मुझे लखनऊ में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ 20 सवालों का लिखित टेस्ट और कूटनीतिक कैमरा-फेसिंग का इंटरव्यू पास करने के बाद जून में मुझे फाइनल सिलेक्शन का कॉल आया।

प्रश्न: जब केबीसी से बुलावा आया, उसी समय आपका यूपीएससी (UPSC) का एग्जाम भी था, तो उस दुविधा को आपने कैसे संभाला?

योगेश साहू: हाँ, अगस्त में मेरा पहला यूपीएससी मेंस का पेपर था और जून में यह कॉल आया। मैं बड़ी दुविधा में था कि केबीसी जाऊँ या नहीं, क्योंकि केबीसी की तैयारी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता और यूपीएससी का मेरा पहला अटेम्प्ट था। लेकिन जब मैंने सोचा कि लोग 20-20 साल तक इसके लिए तरसते हैं और मुझे मौका मिला है, तो मैंने जाने का फैसला किया। मैं दिन भर यूपीएससी पढ़ता था और रोजाना एक घंटा केबीसी के लिए अलग से निकालकर रामायण, महाभारत और क्रिकेट जैसे विषयों की तैयारी करता था।

प्रश्न: अमिताभ बच्चन जी को पहली बार लाइव सामने देखने और हॉट सीट पर बैठने का अनुभव कैसा था?

योगेश साहू: जब टीवी की तरह ही बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ सर की धमाकेदार एंट्री हुई, तो वह बहुत ही अद्भुत अहसास था। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी तरह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट (बजर राउंड) जीतकर हॉट सीट तक पहुँचना है। जब मैं हॉट सीट पर पहुँचा तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। शुरुआती 5-10 सवाल आसान थे, पर 45 सेकंड के समय के कारण मैं बहुत सतर्क था और हर सवाल व ऑप्शन को दो-तीन बार ध्यान से पढ़कर जवाब दे रहा था।

प्रश्न: ₹50 लाख का वह सवाल कौन सा था और 1 करोड़ के सवाल पर क्या कंफ्यूजन हुआ जिसके कारण आपने खेल छोड़ने का फैसला किया?

योगेश साहू: 50 लाख का सवाल एक इमेज आधारित नोबेल पुरस्कार विजेताओं के जन्मस्थान से जुड़ा पैटर्न था, जिसे मैंने लाइफलाइन की मदद से हल किया और 'त्रिची' (तमिलनाडु) सही जवाब दिया। जहाँ तक 1 करोड़ के सवाल की बात है, तो सवाल में पूछा गया था कि 1943 में रेस जीतने वाले 'घोड़े' का नाम क्या था। विकल्पों में एक नाम 'प्रिंसेस ब्यूटीफुल' था। मैंने लॉजिक लगाया कि चूंकि सवाल में 'घोड़ा' पूछा है, तो 'प्रिंसेस' (घोड़ी) वाला विकल्प गलत होगा। बाकी तीन विकल्पों का मुझे कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए रिस्क न लेते हुए मैंने ₹50 लाख लेकर खेल छोड़ना सही समझा। बाद में पता चला कि सही जवाब वही 'प्रिंसेस ब्यूटीफुल' था, जो कि एक घोड़ी थी।

प्रश्न: जब आपका सिलेक्शन देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान 'आईआईटी बॉम्बे' (IIT Bombay) में हुआ, तो उस समय आर्थिक दिक्कतों को लेकर क्या स्थिति थी और प्रशासन से आपको क्या मदद मिली?

योगेश साहू: वह मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। जब मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, तो मेरे परिवार के सामने सबसे बड़ी चिंता कॉलेज की फीस जमा करने की थी। अगर उस वक्त सरकारी मदद नहीं मिलती, तो मुझे भारी-भरकम बैंक लोन लेना पड़ता, जिससे मेरे ऊपर शुरुआत से ही एक बड़ा मानसिक बोझ बन जाता। लेकिन मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उस कठिन समय में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने मेरी इस स्थिति को समझा और तुरंत सहायता राशि मंजूर की। उस आर्थिक मदद ने मेरे सिर से लोन का पूरा प्रेशर हटा दिया, जिसकी वजह से ही मैं कॉलेज के बाद सीधे बिना किसी तनाव के यूपीएससी की तैयारी करने का यह बड़ा फैसला ले पाया।

प्रश्न: आप आईआईटी बॉम्बे के छात्र रहे हैं और लाखों के जॉब ऑफर छोड़कर यूपीएससी में आए, इसके पीछे क्या वजह है?

योगेश साहू: मैंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। जब मैं बेंगलुरु में इंटर्नशिप कर रहा था, तब कॉर्पोरेट लाइफ देखकर मुझे लगा कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जहाँ मैं सीधे जमीन पर लोगों की मदद कर सकूँ। कॉलेज प्लेसमेंट में मेरे साथियों को 1 से 1.5 लाख रुपये महीना की नौकरियां मिल रही थीं, लेकिन मैंने यूपीएससी करने का मन बना लिया था, इसलिए प्लेसमेंट में रजिस्टर ही नहीं किया। आईएएस एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप कई अलग-अलग विभागों में काम

करके सीधे समाज के सबसे निचले तबके की परेशानियों को दूर कर सकते हैं।

प्रश्न: एक छात्र और युवा होने के नाते आप छत्तीसगढ़ की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं?

योगेश साहू: हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता की कमी है। पिछले 2-3 सालों में 'स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूलों' का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और वहाँ के बच्चे टॉप-10 लिस्ट में आ रहे हैं। आत्मानंद स्कूल तो ठीक हैं, लेकिन बस्तर और नारायणपुर जैसे कई अंदरूनी जिलों में स्कूलों की इमारतें टूटी हैं और सुविधाएं बेहद कम हैं। सबसे बड़ी समस्या टीचर ट्रेनिंग की कमी और मॉनिटरिंग न होना है, कई जगहों पर शिक्षक शराब पीकर स्कूल आ रहे हैं। सरकार को योग्य युवाओं के लिए समय पर भर्ती निकालनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूलों में छोटे-छोटे प्रोत्साहन या स्कॉलरशिप की शुरुआत करनी चाहिए।

प्रश्न: अंत में, हमारे अखबार के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

योगेश साहू: मैं 'मैनिफेस्टेशन' (सकारात्मक सोच) पर बहुत विश्वास करता हूँ। सबसे पहला कदम यह है कि आपको खुद पर यह पक्का भरोसा होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, उसे कर सकते हैं। दुनिया माने या न माने, आपके भीतर वो विश्वास होना चाहिए। इसके बाद कड़ी मेहनत और निरंतरता तो जरूरी है ही। इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, बड़ा सोचिए और उसे पूरा करने में जुट जाइए!

बारिश की हर बूंद सहेजने में छत्तीसगढ़ देश में नंबर-1

जल संचय जन भागीदारी के तीसरे चरण में हासिल किया पहला स्थान

रायपुर, 2 सितंबर 2026। बारिश की हर बूंद को सहेजने और उसे धरती के भीतर पहुंचाकर भविष्य के लिए जल सुरक्षित करने की दिशा में छत्तीसगढ़ ने देश के सामने जनभागीदारी का प्रभावी मॉडल पेश किया है। जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश के पांच जिले भी जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं।

नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे नवाचारों और जनभागीदारी आधारित प्रयासों की जानकारी साझा की। सम्मेलन के 'कैच द रेन' सत्र में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और पेयजल स्रोतों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल सहित विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जल संरक्षण को सरकारी योजना नहीं, जनअभियान बनाया : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को केवल सरकारी योजनाओं और जल संरचनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं रखा है। किसानों, ग्राम पंचायतों, जल सखियों, जल मित्रों और स्थानीय समुदायों को जोड़कर इसे व्यापक जनअभियान का रूप दिया गया है।

उन्होंने कहा कि वे स्वयं किसान परिवार से आते हैं और अपने गृहग्राम बगिया में हल चलाकर खेती कर चुके हैं। इसलिए खेती और ग्रामीण जीवन में पानी के महत्व को करीब से समझते हैं। किसान के लिए पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि फसल, परिवार, आजीविका और भविष्य से जुड़ा विषय है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण की योजनाओं के केंद्र में किसान और गांव को रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में करीब 4 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला छत्तीसगढ़ 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह उपलब्धि सिर्फ जल संरचनाओं की संख्या नहीं, बल्कि प्रदेश में जल संरक्षण को लेकर बढ़ती सामूहिक चेतना और जनभागीदारी का भी परिणाम है।

कोरिया से निकला '5 प्रतिशत मॉडल', किसान खुद दे रहे जमीन

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में कोरिया जिले से शुरू हुए '5 प्रतिशत मॉडल' का विशेष उल्लेख किया। इसे जल संरक्षण में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी का अनूठा उदाहरण माना जा रहा है।

इस पहल के तहत किसान अपनी कृषि भूमि का करीब 5 प्रतिशत हिस्सा भू-जल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए स्वेच्छा से उपलब्ध करा रहे हैं। इस हिस्से में ऐसी जल संरचनाएं विकसित की जा रही हैं, जहां बारिश का पानी खेत से बाहर बहने के बजाय वहीं रुक सके और धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंच सके।

इस मॉडल की खासियत यह है कि किसान सिर्फ योजना के लाभार्थी नहीं, बल्कि जल संरक्षण अभियान के सक्रिय भागीदार हैं। किसान जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, पंचायतें और स्थानीय समुदाय सहयोग कर रहे हैं तथा विभिन्न विभागों और योजनाओं के समन्वय से जल संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

जल संरचनाओं की जियो-टैगिंग, नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा को भी अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। जल सखी, जल मित्र, किसान और पंचायत प्रतिनिधि गांवों में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं।

JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम

जल शक्ति मंत्रालय के 'जल संचय जन भागीदारी' अभियान के तीनों चरणों में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। पहले दो चरणों में देश में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद तीसरे चरण में प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

JSJB 1.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 4 लाख 5 हजार 561 जल संरचनाएं बनाई गईं। इस चरण में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर रहा।

JSJB 2.0 में प्रदेश में 24 लाख 7 हजार 456 जल संरचनाएं दर्ज की गईं। इनमें से 23 लाख 7 हजार 768 संरचनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। इस चरण में भी छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया।

वहीं JSJB 3.0 में छत्तीसगढ़ ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। इस चरण में प्रदेश में 79 हजार 775 जल संरचनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें से 77 हजार 719 का कार्य पूरा हो चुका है। इन प्रयासों का उद्देश्य बारिश के पानी को बहकर बाहर जाने से रोकना, उसका स्थानीय स्तर पर उसका संचयन करना और अधिक से अधिक पानी को जमीन के भीतर पहुंचाना है।

छत्तीसगढ़ के पांच जिले देश के टॉप-10 में

राज्य स्तर की उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ के जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बलौदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं।

इन जिलों में जल संरक्षण को स्थानीय समुदायों से जोड़ते हुए गांव और पंचायत स्तर पर वर्षा जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण के कार्य किए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार जल संरचनाएं विकसित करने के साथ लोगों की भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि बताती है कि जब सरकारी योजनाओं के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जुड़ती है, तो जल संरक्षण जैसे बड़े लक्ष्य को भी जनआंदोलन का रूप दिया जा सकता है।

पानी की कमी वाले ब्लॉक 26 से घटकर 19 हुए

प्रदेश में किए जा रहे जल संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पानी की कमी वाले ब्लॉकों की संख्या 26 से घटकर 19 रह गई है। इसके अलावा पांच क्रिटिकल ब्लॉकों के भी सामान्य श्रेणी में आने का अनुमान है।

भू-जल स्थिति में सुधार के लिए राज्य में जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों के संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, जल संरचनाओं की मैपिंग और स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना हुआ साकार, 3.65 लाख अतिरिक्त पीएम आवासों की सौगात

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार करने की दिशा में एक और बड़ी पहल हुई है। सक्ती में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों में हितग्राही परिवारों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतीकात्मक रूप से हितग्राहियों को उनके नए घरों की चाबी सौंपी।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की सौगात दी। साथ ही नवगठित सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की। बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा भी 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति का पत्र केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सौंपा।

छत्तीसगढ़ में हर दिन 1600 से ज्यादा आवास पूरे हो रहे

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण इसी संकल्प को जमीन पर उतारने वाली महत्वपूर्ण योजना है।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण तेजी से हो रहा है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूरे किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी सराहना की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है। केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास के साथ सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल गरीब परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। आवासों के साथ उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है।

पिछले ढाई साल में 11.50 लाख से ज्यादा आवास पूरे

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी।

उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास सर्वे-2011 और आवास प्लस सर्वे के तहत आवासों के लक्ष्य की स्वीकृति मिल चुकी है। अब आवास प्लस-प्लस सर्वे में शामिल शेष पात्र परिवारों के लिए भी आवास स्वीकृत कराने का प्रयास किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव 2026
साख की लड़ाई और दिग्गजों की अग्निपरीक्षा

छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों (4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत) में चुनाव होने हैं। यह चुनाव महज़ स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं रह गए हैं, बल्कि यह सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के संगठनात्मक कौशल का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए चुनाव प्रभारियों, सह-प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की फौज मैदान में उतार दी है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इन चुनावों के परिणाम राज्य की भावी राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

2025 के परिणाम और आखिरी किलों को बचाने की जद्दोजहद

इस आगामी मुकाबले की गंभीरता और वर्तमान चुनौतियों को समझने के लिए करीब डेढ़ साल पहले, फरवरी 2025 में संपन्न हुए वृहद नगरीय निकाय चुनावों के परिणामों का विश्लेषण आवश्यक है। 2025 के उस चुनाव में भाजपा ने एकतरफा सुनामी लाते हुए प्रदेश के सभी 10 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया था और 49 में से 35 नगर पालिकाओं व अधिकांश नगर पंचायतों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था। उस प्रचंड हार के बाद कांग्रेस के लिए यह चुनाव संजीवनी की तरह है। वर्तमान में जिन 15 निकायों में चुनाव होने हैं, वहां दिसंबर 2021 के परिणामों के आधार पर कांग्रेस का मजबूत दबदबा रहा है और चारों निगमों (बीरगांव, भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरौदा) में उसी के महापौर काबिज है। ऐसे में कांग्रेस के सामने अपने अंतिम शहरी गढ़ों को बचाने की विशाल चुनौती है, जबकि भाजपा 2025 के अपने 'क्लीन स्वीप' अभियान को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है।

कांग्रेस का दिग्गजों पर दांव, दो निकायों में महिला पर्यवेक्षक

इस वर्चस्व की लड़ाई के लिए दोनों दलों ने अपने सबसे अनुभवी और कद्दावर नेताओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देते हुए महत्वपूर्ण नगर निगमों में वरिष्ठ पर्यवेक्षकों को मोर्चे पर तैनात किया है। बीरगांव नगर निगम की जिम्मेदारी डॉ. शिवकुमार डहरिया को सौंपी गई है, जबकि भिलाई शहर के लिए धनेन्द्र साहू और रिसाली के लिए मोहन मरकाम

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी
आसन्न नगरीय निकाय चुनाव – 2026
पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षकगण

जिला कांग्रेस कमेटी	क्र.	नगर निगम	पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षकों के नाम	
रायपुर ग्रामीण	1	बीरगांव	पर्यवेक्षक	डॉ. शिवकुमार डहरिया
			सह–पर्यवेक्षक	श्री मोतीलाल देवांगन
				श्री लेखराम साहू
भिलाई शहर	2	भिलाई	पर्यवेक्षक	श्री धनेन्द्र साहू
			सह–पर्यवेक्षक	श्री दीपक दुबे
भिलाई शहर	3	रिसाली	पर्यवेक्षक	श्री मोहन मरकाम
			सह–पर्यवेक्षक	श्री कन्हैया अग्रवाल
दुर्ग ग्रामीण	4	भिलाईचरौदा	पर्यवेक्षक	श्री विकास उपाध्याय
			सह–पर्यवेक्षक	श्री राजेन्द्र साहू

जिला	क्र.	नगर पालिका	पर्यवेक्षक का नाम
कोरिया	1	बैकुण्ठपुर	श्री राघवेन्द्र सिंह
कोरिया	2	शिवपुर चरचा	श्री प्रशांत मिश्रा
सारंगढ़–बिलाईगढ़	3	सारंगढ़	श्रीमती चातुरी नंद
दुर्ग ग्रामीण	4	जामुल	श्री प्रमोद दुबे
खैरागढ़–गंडई–छुईखदान	5	खैरागढ़	श्रीमती छन्नी साहू

जिला	क्र.	नगर पंचायत	पर्यवेक्षक का नाम
सूरजपुर	1	प्रेमनगर	श्री भानुप्रताप सिंह
बेमेतरा	2	मारो	श्री सुनील महेश्वरी
कांकेर	3	नरहरपुर	श्री आनंद पवार
सुकमा	4	कोन्टा	श्री अवधेश गौतम
बीजापुर	5	भैरमगढ़	श्री रेखचंद जैन
बीजापुर	6	भोपालपट्नम	श्री सत्तार अली

(मलकीत सिंह गैंदू)
प्रभारी महामंत्री (संगठन एवं प्रशा.)

जैसे दिग्गजों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। भिलाई-चरौदा निगम में जीत का खाका तैयार करने का जिम्मा विकास उपाध्याय को दिया गया है। वहीं चुनावी प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कांग्रेस ने केवल दो निकाय खैरागढ़ और सारंगढ़ के लिए महिला पर्यवेक्षक नियुक्त किया है; जिसमें खैरागढ़ की कमान छन्नी साहू और सारंगढ़ की जिम्मेदारी चातुरी नंद को सौंपी गई है। इसके अलावा बैकुंठपुर जैसे निकायों में राघवेन्द्र सिंह पर भरोसा जताया गया है।

भाजपा का आक्रामक रुख: हर निकाय में महिला सह-प्रभारी अनिवार्य

दूसरी ओर, भाजपा ने 2025 के अपने विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए आक्रामक रूप से प्रभारियों और सह-प्रभारियों की सूची जारी की है। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भाजपा की रणनीति इस बार बेहद स्पष्ट और व्यापक नजर आ रही है। पार्टी ने 'आधी आबादी' को साधने के लिए हर निकाय में नियुक्त किए गए दो सह-प्रभारियों में से एक पद पर अनिवार्य रूप से महिला नेत्रियों को जिम्मेदारी दी है। बीरगांव निगम में कांग्रेस को घेरने के लिए सौरभ सिंह को प्रभारी तथा भावना बोहरा और कमल गर्ग को सह-प्रभारी

प्रभारी–सहप्रभारी का नाम

क्र.	जिला	निकाय का नाम	प्रभारी–सहप्रभारी का नाम	पद
1	रायपुर	नगर निगम बीरगांव	श्री सौरभ सिंह	प्रभारी
			श्रीमती भावना बोहरा	सहप्रभारी
			श्री कमल गर्ग	सहप्रभारी
2	दुर्ग	नगर निगम भिलाई	श्री भूपेन्द्र सवन्नी	प्रभारी
			श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	सहप्रभारी
			श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी	सहप्रभारी
3		नगर निगम रिसाली	श्री अनुराग सिंह देव	प्रभारी
			श्रीमती श्वेता शर्मा	सहप्रभारी
			श्री आसु चंद्रवंशी	सहप्रभारी
4		नगर निगम भिलाई–चरौदा	श्री नीलू शर्मा	प्रभारी
			श्रीमती मीनल चौबे	सहप्रभारी
			श्री सूर्यकांत राठौर	सहप्रभारी
5		नगरपालिका जामुल	श्री राजीव अग्रवाल	प्रभारी
			श्रीमती अलका बाघमारे	सहप्रभारी
			श्री अशोक साहू	सहप्रभारी
6	बेमेतरा	नगर पंचायत मारो	श्री राजा पाण्डेय	प्रभारी
			डॉ. सनम जांगड़े	सहप्रभारी
			श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी	सहप्रभारी
7	खैरागढ़ छुईखदान गडई	नगरपालिका खैरागढ़	श्री लाभचंद बाफना	प्रभारी
			श्री ओमप्रकाश जोशी	सहप्रभारी
			श्रीमती किरण साहू	सहप्रभारी
8	सारंगढ़–बिलाईगढ़	नगरपालिका सारंगढ़	श्री रजनीश सिंह	प्रभारी
			श्री उमेश अग्रवाल	सहप्रभारी
			श्रीमती पूनम सोलंकी	सहप्रभारी
9	सूरजपुर	नगर पंचायत प्रेमनगर	श्री ललनप्रताप सिंह	प्रभारी
			श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते	सहप्रभारी
			श्री अंबिकेश केशरी	सहप्रभारी
10	कोरिया	नगरपालिका बैकुण्ठपुर	श्री बाबूलाल अग्रवाल	प्रभारी
			श्रीमती मंजूषा भगत	सहप्रभारी
			श्री डमरू बेहरा	सहप्रभारी
			श्री प्रीतेश गांधी	सहप्रभारी
13	सुकमा	नगर पंचायत कोण्टा	श्री रामाश्रय सिंह	प्रभारी
			श्री संग्राम सिंह राणा	सहप्रभारी
			श्रीमती जमुना मांझी	सहप्रभारी
14	बीजापुर	नगर पंचायत भैरमगढ़	श्री चैतराम अटामी	प्रभारी
			श्रीमती पायल गुप्ता	सहप्रभारी
			श्री दीपक पाजपेयी	सहप्रभारी
15		नगर पंचायत भोपालपट्नम	श्री जी. वैंकटेश्वर राव	प्रभारी
			श्रीमती जानकी कोरसा	सहप्रभारी
			श्री श्रीनिवास मुदलियार	सहप्रभारी

(डॉ. नवीन मारकण्डेय)
प्रदेश महामंत्री एवं
मुख्यालय प्रभारी

नियुक्त किया गया है। भिलाई और रिसाली जैसे हाई-प्रोफाइल निगमों में क्रमशः भूपेन्द्र सवन्नी और अनुराग सिंह देव को कमान सौंपी गई है। भिलाई-चरौदा में नीलू शर्मा मुख्य रणनीतिकार की भूमिका में होंगे। भाजपा ने सुदूर बस्तर और अन्य क्षेत्रों की नगर पंचायतों में भी मजबूत घेराबंदी की है; कोंटा में रामाश्रय सिंह, भैरमगढ़ में चैतराम अटामी और भोपालपट्नम में जी. वेंकटेश्वर राव को प्रभारी बनाकर जमीन पर उतारा गया है।

नेताओं के राजनीतिक कद की असली अग्निपरीक्षा

राजनीतिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से देखें तो इन प्रभारियों और पर्यवेक्षकों के लिए यह चुनाव उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कद की भी अग्निपरीक्षा है। इन प्रमुख चेहरों पर जीत दिलाने की भारी जिम्मेदारी है। यदि ये नेता अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में पार्टी का झंडा फहराने में सफल होते हैं, तो संगठन और सत्ता के भीतर उनका कद कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं, हार की स्थिति में उनकी नेतृत्व क्षमता पर सीधे सवाल उठेंगे। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी-इनकंबेंसी के असर को कम करना और कार्यकर्ताओं में 2025 की हार के बाद नया उत्साह भरना है। वहीं भाजपा का लक्ष्य महिलाओं की मजबूत भागीदारी और संगठन के बेहतर तालमेल से कांग्रेस के इन आखिरी किलों को ध्वस्त करना है। जैसे-जैसे साल का अंत करीब आ रहा है, छत्तीसगढ़ के इन 15 निकायों की बिसात पर बिछी यह राजनीतिक गोटियां एक बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर का संकेत दे रही हैं।

नगरीय निकाय चुनाव 2021 का परिणाम

नगर निगम

क्रम	वांर्ड/नगर निगम	कांग्रेस	भाजपा	निर्दलीय
1	भिलाई (70 सीट)	37	22	11
2	भिलाई-चरौदा (40)	19	15	06
3	बीरगांव (40 सीट)	19	10	11
4	रिसाली (40 सीट)	21	12	07

नगर पंचायत

क्रम	नगर पंचायत	कांग्रेस	भाजपा	निर्दलीय
1	कोंटा (15 सीट)	14	1	0
2	भोपालपट्नम (15)	15	0	0
3	भैरमगढ़ (15 सीट)	12	3	0
4	नरहरपुर (15 सीट)	11	4	0
5	प्रेमनगर (15 सीट)	11	2	2
6	मारो (15 सीट)	10	4	1

नगर पालिका परिषद

क्रम	नगर पालिका परिषद	कांग्रेस	भाजपा	निर्दलीय
1	बैकुंठपुर (20 सीट)	11	7	2
2	शिवपुर-चरचा (15)	8	5	2
3	सांरगढ़ (15 सीट)	11	3	1
4	जामुल (20 सीट)	6	10	4
5	खैरागढ़ (20 सीट)	10	10	0

बिलासपुर हाईकोर्ट के 16 चीफ जस्टिस जानिए किसका कितना रहा कार्यकाल

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भारत के नए उच्च न्यायालयों में से एक है। इसे 1 नवंबर 2000 को 'मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000' के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका अधिकार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के इलाकों पर है। बिलासपुर स्थित यह उच्च न्यायालय भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। इस उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1 नवंबर 2000 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल ने किया था।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थापना के बाद अब तक 16 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल चुके हैं। इनमें वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्र 16वें चीफ जस्टिस के रूप में हैं।

हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, पहले स्थायी चीफ जस्टिस जस्टिस डब्ल्यू.ए. शिशाक बने। उन्होंने 5 दिसंबर 2000 से 15 जनवरी 2002 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इससे पहले जस्टिस आर.एस. गर्ग ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाली थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रहे

स्थायी मुख्य न्यायाधीशों की सूची से अलग,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुछ अवसरों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों ने भी जिम्मेदारी संभाली। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जस्टिस आर.एस. गर्ग ने 1 नवंबर 2000 से 1 नवंबर 2001 तक और जस्टिस जगदीश भल्ला ने 19 मई 2007 से 1 फरवरी 2008 तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया।

बैठक के बाद यह तस्वीर साफ होगी कि राज्य प्रशासनिक सेवा के किन अधिकारियों को IAS कैडर में पदोन्नति का अवसर मिलता है। इससे संबंधित अधिकारियों के प्रशासनिक करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।

क्रम	मुख्य न्यायाधीश	कार्यकाल	लगभग अवधि
1	डब्ल्यू.ए. शिशाक	05.12.2000 – 15.01.2002	1 साल 1 माह
2	के.एच.एन. कुरंगा	06.02.2002 – 10.05.2004	2 साल 3 माह
3	ए.एस.वी. मूर्ति	28.05.2004 – 07.01.2005	7 माह
4	ए.के. पटनायक	14.03.2005 – 01.10.2005	6 माह
5	एस.आर. नायक	17.11.2005 – 31.12.2006	1 साल 1 माह
6	एच.एल. दत्तू	12.02.2007 – 17.05.2007	3 माह
7	राजीव गुप्ता	02.02.2008 – 09.10.2012	4 साल 8 माह
8	यतींद्र सिंह	22.10.2012 – 08.10.2014	1 साल 11 माह
9	नवीन सिन्हा	09.04.2015 – 11.05.2016	1 साल 1 माह
10	दीपक गुप्ता	16.05.2016 – 16.02.2017	9 माह
11	टी.बी. राधाकृष्णन	18.03.2017 – 06.07.2018	1 साल 3 माह
12	अजय कुमार त्रिपाठी	07.07.2018 – 26.03.2019	8 माह
13	पी.आर. रामचंद्र मेनन	06.05.2019 – 31.05.2021	2 साल
14	अरूप कुमार गोस्वामी	12.10.2021 – 10.03.2023	1 साल 5 माह
15	रमेश सिन्हा	29.03.2023 – 04.09.2026	3 साल 5 माह
16	कृष्ण राम महापात्र	07.09.2026 – वर्तमान	वर्तमान

न्याय सबके लिए

खास बात : यह सूची छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की आधिकारिक पूर्व मुख्य न्यायाधीश सूची पर आधारित है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अफसर बन सकते हैं IAS

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जल्द ही करियर से जुड़ा बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली में होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में राज्य के अधिकारियों को IAS अवार्ड देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

इस बैठक के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के किन पात्र अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया पर प्रदेश के कई अधिकारियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

UPSC चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी बैठक

IAS अवार्ड की प्रक्रिया को लेकर दिल्ली में होने वाली DPC बैठक की अध्यक्षता UPSC चेयरमैन डॉ. अजय कुमार करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी सचिव मुकेश बंसल भी शामिल होंगे।

DPC की बैठक को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी प्रक्रिया के तहत पात्र अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर IAS कैडर में पदोन्नति के लिए नामों पर विचार किया जाता है।

पिछले साल तीन अधिकारियों को मिला था IAS अवार्ड

जानकारी के अनुसार, संबंधित बैच में कुल 29 अधिकारी शामिल हैं। इनमें से पिछले साल तीन अधिकारियों को IAS अवार्ड दिया जा चुका है। इनमें सुमित अग्रवाल, संदीप अग्रवाल और आशीष टिकरिया के नाम शामिल हैं।

अब इसी प्रक्रिया के अगले चरण में बचे हुए पात्र अधिकारियों के नामों पर विचार किए जाने की संभावना है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों के बीच DPC के निर्णय को लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है।

तीन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा

इस बार संभावित दावेदारों में अभिषेक अग्रवाल, सचिन भूतड़ा और राजीव पांडे के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में इस वर्ष राज्य प्रशासनिक सेवा से IAS बनने के लिए पांच पद उपलब्ध हैं।

हालांकि, दो अधिकारियों से जुड़े कुछ मामलों के चलते उनके नामों पर सहमति बनने की संभावना कम बताई जा रही है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो उपलब्ध पांच पदों में से तीन पदों पर ही IAS अवार्ड दिए जाने की संभावना बन सकती है।

DPC के फैसले पर टिकी नजरें

फिलहाल अंतिम निर्णय DPC की बैठक में होने वाली चर्चा और निर्धारित नियमों के तहत पात्रता के आकलन के बाद ही सामने आएगा। इसलिए संभावित नामों को लेकर चल रही चर्चाओं के बावजूद अंतिम सूची का इंतजार करना होगा।

हुनर को मिला बिहान का साथ, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ीं रानू कैवर्त

सिलाई और किराना दुकान से लेकर बटेर-मुर्गी पालन व हैचरी तक कई आजीविका गतिविधियां, सालाना 2 से 3 लाख रुपये की आय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे सरकारी प्रयासों का सकारात्मक असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-बिहान से जुड़कर महिलाएं अपने हुनर और मेहनत को स्थायी आजीविका का माध्यम बना रही हैं। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही विकासखंड की ग्राम पंचायत अंडी की रानू कैवर्त ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने मेहनत, हुनर और बिहान से मिले सहयोग के दम पर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है।

कभी सीमित आमदनी में परिवार की जरूरतें पूरी करने वाली रानू कैवर्त आज गांव में महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। शिव गुरु महिला स्व-सहायता समूह की सचिव के रूप में उन्होंने समूह से मिले मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग का बेहतर उपयोग करते हुए आजीविका की कई गतिविधियों को आगे बढ़ाया। उनके प्रयासों का नतीजा है कि विभिन्न आयमूलक गतिविधियों से अब उनकी सालाना आय करीब 2 से 3 लाख रुपये तक पहुंच गई है और वे 'लखपति दीदी' बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

एक नहीं, कई आजीविका गतिविधियों से बढ़ी आमदनी

रानू कैवर्त ने आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी एक व्यवसाय पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रुचि और स्थानीय जरूरतों के अनुसार कई गतिविधियों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। उनके समूह की ओर से सिलाई कार्य, कपड़ों की दुकान, किराना स्टोर, बटेर पालन, देशी मुर्गी पालन और हैचरी जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

सिलाई और कपड़ों की दुकान ने उन्हें अपने हुनर को आमदनी में बदलने का अवसर दिया। वहीं किराना दुकान, बटेर पालन और देशी मुर्गी पालन से आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार हुए। हैचरी जैसी गतिविधियों ने उनके काम को और विस्तार दिया।

अलग-अलग गतिविधियों को आपस में जोड़कर रानू ने ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय बाजार की संभावनाओं का बेहतर उपयोग किया है। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिली।

बिहान से मिला अवसर, मेहनत ने बदली तस्वीर

रानू बताती हैं कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें अपनी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर मिला। बिहान से मिले आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समूह की सामूहिक शक्ति ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया।

उन्होंने सरकारी सहयोग को अपनी मेहनत और लगन के साथ जोड़ा और धीरे-धीरे आजीविका के कई साधन विकसित किए। उनकी कहानी बताती है कि ग्रामीण महिलाओं को यदि अवसर, संसाधन, प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिले तो वे न केवल खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर सकती हैं।

रानू का सफर अब गांव की दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। उनके प्रयास महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जुड़कर अपने हुनर को आजीविका में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

महतारी वंदन योजना से मिला अतिरिक्त संबल

रानू कैवर्त को महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ भी मिल रहा है। नियमित आर्थिक सहयोग से उन्हें घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इससे उनका आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ा है और वे अपनी आजीविका गतिविधियों को विस्तार देने पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभार

रानू कैवर्त ने अपनी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और बिहान से मिले सहयोग ने उनके जैसे ग्रामीण परिवारों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है।

आज रानू अपने हुनर और मेहनत के दम पर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। 'लखपति दीदी' बनने की दिशा में बढ़ते उनके कदम ग्रामीण छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की बदलती तस्वीर को सामने रखते हैं।

रानू की कहानी यह संदेश देती है कि सही अवसर, प्रशिक्षण, सहयोग और प्रोत्साहन मिलने पर ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था और सामाजिक बदलाव की भी मजबूत वाहक बन सकती हैं।

बिहान ने बदली महिलाओं की जिंदगी, आत्मनिर्भर बनकर लिख रहीं सफलता की नई कहानी

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ के गांव-देहात की महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) आत्मनिर्भरता की नई राह बनकर सामने आया है। कभी आय के स्थायी साधन के लिए परिवार पर निर्भर रहने वाली महिलाएं आज स्व-सहायता समूहों से जुड़कर रोजगार और स्वरोजगार के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं।

बिहान योजना के माध्यम से महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण, कौशल विकास प्रशिक्षण और व्यवसाय शुरू करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका लाभ उठाकर महिलाएं पशुपालन, मुर्गी पालन, जैविक खेती, सिलाई-बुनाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण जैसे अलग-अलग कामों से जुड़ रही हैं।

मेहनत बनी कमाई का जरिया

बिहान से जुड़ने के बाद महिलाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं मिला, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी है। अपने हुनर और मेहनत के दम पर महिलाएं नियमित आमदनी अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इन महिलाओं की कमाई से बच्चों की पढ़ाई, घर की जरूरतें और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में भी मदद मिल रही है। यानी महिला की आत्मनिर्भरता का असर सिर्फ उसके जीवन पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य पर दिखाई दे रहा है।

आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ा सम्मान

योजना से लाभान्वित महिलाओं का कहना है कि बिहान से जुड़ने से पहले उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। आज वे खुद कमाई कर रही हैं और अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ समाज में उनका मान-सम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा है।

इन महिलाओं की कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर अवसर, प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण महिलाएं भी अपनी मेहनत और हुनर के दम पर सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं।

प्रेरणा देती है सफलता की यह कहानी

बिहान योजना से जुड़ी महिलाओं की सफलता उन हजारों ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती हैं। यह कहानी बताती है कि छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव की नींव बन सकती है।

आज दंतेवाड़ा की ये महिलाएं सिर्फ अपने परिवार का सहारा नहीं बन रहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रही हैं।

अपराध पीड़ितों की क्षतिपूर्ति पर हाईकोर्ट सख्त: 1099 मामलों में ₹37.07 करोड़ अब भी लंबित, सरकार से पूछा-आखिर कब मिलेगा हक ?

बिलासपुर। अपराध का शिकार होने के बाद पीड़ितों को न्याय की उम्मीद अदालत से होती है, लेकिन जब अदालत से राहत मिलने के बावजूद क्षतिपूर्ति की राशि वर्षों तक अटकी रहे, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत 1099 मामलों में कुल 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की राशि अब तक पात्र पीड़ितों को नहीं मिल सकी है।

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह कोई एक-दो मामलों की देरी नहीं, बल्कि हजार से ज्यादा अपराध पीड़ितों के हक की करोड़ों रुपये की राशि का मामला है। सरकार की ओर से लंबे समय से कार्रवाई किए जाने और फंड उपलब्ध होते ही भुगतान करने का भरोसा अदालत को दिया जाता रहा है, लेकिन बड़ी राशि अब भी लंबित है।

डेढ़ साल से कार्रवाई का भरोसा, लेकिन भुगतान का इंतजार कायम

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच इस मामले की लगातार निगरानी कर रही है। अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच हुई सुनवाइयों में सरकार की ओर से बताया गया कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के तहत राशि आवंटित करने और पात्र लोगों तक भुगतान पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार ने यह भी कहा कि जैसे ही फंड उपलब्ध होगा, लंबित राशि जारी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि पीड़ितों के लिए 'फंड उपलब्ध होते ही' का इंतजार आखिर कितना लंबा चलेगा?

कागजों में कार्रवाई आगे बढ़ती रही, लेकिन जमीन पर 1099 मामलों में करोड़ों रुपये की राशि लंबित रह गई। यही स्थिति अब हाईकोर्ट की सख्ती का कारण बनी है।

हाईकोर्ट ने मांगा हिसाब, अधिकारी को देना होगा व्यक्तिगत शपथपत्र

अदालत ने अब केवल सामान्य जवाब से संतुष्ट होने के बजाय सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अधिकारी को बताना होगा कि 37.07 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने के लिए अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं। साथ ही अदालत ने शेष राशि के भुगतान की स्पष्ट समयसीमा भी बताने को कहा है।

यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं होगा कि "कार्रवाई चल रही है या नहीं?" बल्कि यह भी बताना होगा कि कार्रवाई क्या हुई, कितना हुआ और पीड़ितों को पैसा कब तक मिलेगा।

अलग बजट हेड बना, फिर भी करोड़ों अटके

मामले की पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी थी कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के लिए अलग बजट हेड तैयार किया गया है।

लेकिन अलग बजट हेड बनने के बाद भी अगर 1099 मामलों में 37 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि लंबित है, तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर बजट का प्रावधान बनाने और वास्तविक भुगतान करने के बीच इतनी लंबी दूरी क्यों है?

पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति सिर्फ पैसा नहीं

यह समझना जरूरी है कि अपराध पीड़ित को मिलने वाली क्षतिपूर्ति महज सरकारी भुगतान नहीं है। कई मामलों में यही राशि पीड़ित या उसके परिवार को इलाज, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार के खर्च और आर्थिक संकट से उबरने में मदद कर सकती है।

अपराध के बाद पीड़ित पहले ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान झेल चुका होता है। ऐसे में क्षतिपूर्ति के लिए उसे सरकारी प्रक्रिया और फंड का इंतजार कराना उसके जख्म पर इंतजार की एक और परत जोड़ने जैसा है।

तंज यह कि 'प्रक्रिया जारी है' से पेट नहीं भरता

सरकारी व्यवस्था में अक्सर "प्रक्रिया जारी है", "आवश्यक कार्रवाई की जा रही है" और "फंड उपलब्ध होते ही भुगतान किया जाएगा" जैसे जवाब सुनने को मिलते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का हक करोड़ों की सरकारी फाइल में अटका हो, उसके लिए ये शब्द राहत नहीं बन सकते।

कागज पर कार्रवाई की गति चाहे जितनी तेज हो, पीड़ित तक पैसा पहुंचने के बाद ही उस कार्रवाई का वास्तविक अर्थ साबित होगा।

23 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की है। इस दौरान सक्षम अधिकारी के व्यक्तिगत शपथपत्र के आधार पर सरकार की कार्रवाई और प्रस्तावित समयसीमा की समीक्षा की जाएगी।

न्याय सिर्फ फैसला सुनाने से पूरा नहीं होता

यह मामला शासन-प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि न्याय की प्रक्रिया केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है। यदि किसी पात्र पीड़ित को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि वर्षों तक सरकारी प्रक्रिया, बजट या फंड की कमी में फंसी रहे, तो न्याय की अंतिम कड़ी अधूरी रह जाती है।

हाईकोर्ट की सख्ती इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सरकार को आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई और समयसीमा बतानी होगी।

37.07 करोड़ रुपये और 1099 मामले सिर्फ आंकड़े नहीं हैं-इनके पीछे अपराध से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी जुड़ी है। अब देखना यह है कि 23 सितंबर की अगली सुनवाई तक फाइलों में चल रही कार्रवाई वास्तव में पीड़ितों के खातों तक पहुंचती है या फिर एक बार फिर 'जल्द भुगतान' का भरोसा ही मिलता है।

रायपुर ग्रामीण में अपराध घटे लेकिन हत्या और अपहरण के मामले बढ़े

• **शशिकला साहू,** संवाददाता, रायपुर

रायपुर। 23 जनवरी 2026 से रायपुर की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। रायपुर जिले की पुलिस व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और पुलिस जिला रायपुर ग्रामीण की व्यवस्था लागू की गई। शहरी क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में कमिश्नरेट व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अलग पुलिस जिला बनाया गया। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी हुई।

इस नई व्यवस्था में रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत 12 थाने रखे गए हैं। इनमें विधानसभा, धरसींवा, खरोरा, तिल्दा-नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा-नवापारा और उरला का नगर निगम सीमा से बाहर वाला क्षेत्र शामिल है।

इसी नए पुलिस जिले के आंकड़ों में 23 जनवरी से 31 अगस्त 2025 और 23 जनवरी से 31 अगस्त 2026 की अवधि की तुलना की गई है। 2025 में कुल 2,329 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2026 में यह संख्या घटकर 2,131 रह गई। यानी 198 मामले कम हुए और कुल आपराधिक प्रकरणों में 8.50 प्रतिशत की कमी आई।

चोट के सबसे ज्यादा मामले

आंकड़ों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चोट के मामलों की है। 2025 में 918 मामले दर्ज हुए, जो कुल अपराध का 39.42 प्रतिशत था। 2026 में मामले घटकर 712 हुए और कुल अपराध में इसकी हिस्सेदारी 33.41 प्रतिशत रह गई। यानी मामलों में 22.44 प्रतिशत की कमी आई।

इसके बाद अन्य भादवि के 400 मामले 2025 में थे, जो कुल का 17.17 प्रतिशत थे। 2026 में यह संख्या बढ़कर 431 हो गई और हिस्सेदारी 20.23 प्रतिशत हो गई। यानी 7.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अपहरण में 17.27% की बढ़ोतरी

ग्रामीण पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता अपहरण/व्यपहरण के आंकड़े हैं। 2025 में 139 मामले यानी कुल अपराध का 5.97 प्रतिशत दर्ज हुए थे। 2026 में मामले बढ़कर 163 हो गए और कुल अपराध में हिस्सेदारी 7.65 प्रतिशत पहुंच गई। यानी 24 मामले अधिक और 17.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

हत्या के प्रयास में 55.56 प्रतिशत की वृद्धि

हत्या के मामले 27 से घटकर 25 हुए। कुल अपराध में इनकी हिस्सेदारी लगभग 1.16 से बढ़कर 1.17 प्रतिशत रही और मामलों में 7.41 प्रतिशत की कमी हुई।

लेकिन हत्या के प्रयास के मामले 18 से बढ़कर 28 हो गए। यानी 10 मामले ज्यादा और वृद्धि दर 55.56 प्रतिशत रही। कुल अपराध में इसकी हिस्सेदारी भी 0.77 प्रतिशत से बढ़कर 1.31 प्रतिशत हो गई।

बलात्कार के मामले घटे, शीलभंग बढ़े

बलात्कार के मामले 68 से घटकर 58 हुए। कुल अपराध में हिस्सेदारी 2.92 से घटकर 2.72 प्रतिशत हुई और मामलों में 14.71 प्रतिशत की कमी आई।

इसके विपरीत शीलभंग के मामले 27 से बढ़कर 34 हुए। कुल अपराध में हिस्सेदारी 1.16 से बढ़कर 1.60 प्रतिशत हो गई। मामलों में 25.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ के मामले भी 5 से बढ़कर 6 हुए, यानी 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चोरी और नकबजनी में राहत

चोरी के मामले 216 से घटकर 196 हुए। कुल अपराध में इसकी हिस्सेदारी 9.27 से घटकर 9.20 प्रतिशत रही और मामलों में 9.26 प्रतिशत की कमी हुई।

नकबजनी 121 से घटकर 102 हुई। कुल अपराध में हिस्सेदारी 5.20 से घटकर 4.79 प्रतिशत और मामलों में 15.70 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।

बलवा भी 30 से घटकर 24 हुआ, यानी 20 प्रतिशत कमी।

आंकड़ों की बड़ी तस्वीर

रायपुर ग्रामीण पुलिस के इन आंकड़ों के मुताबिक कुल अपराध में 8.50 प्रतिशत की कमी निश्चित रूप से आई है, लेकिन इसका बड़ा कारण चोट के मामलों में आई 206 मामलों की कमी है।

दूसरी ओर गंभीर अपराधों की कुछ श्रेणियों में बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर हत्या के प्रयास में 55.56 प्रतिशत, अपहरण में 17.27 प्रतिशत, शीलभंग में 25.93 प्रतिशत और लूट में 13.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वहीं आपराधिक मानव वध, दहेज मृत्यु, अमानत में खयानत, आगजनी, बलवा, नकबजनी और बलात्कार जैसे कई मामलों में गिरावट दर्ज हुई है।

रायपुर में नई पुलिस व्यवस्था

23 जनवरी 2026 से लागू व्यवस्था में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत 21 थाने और रायपुर ग्रामीण पुलिस जिले के अंतर्गत 12 थाने हैं। यानी दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर इस पुलिस पुनर्गठन में 33 थाना क्षेत्रों का ढांचा सामने आया।

दिनकर की हुंकार से कुमार विश्वास की वाणी तक : हिंदी के गौरव की अनवरत यात्रा

हिन्दी दिवस विशेष

• दीप सारस्वत

किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी सीमाओं, इतिहास और भूगोल से नहीं बनती। उसकी भाषा और साहित्य भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। भाषा वह धरोहर है, जिसमें कोई सभ्यता अपनी स्मृतियां संजोती है, संस्कारों को पीढ़ियों तक पहुंचाती है और भविष्य के सपनों को शब्द देती है।

भारत की साहित्यिक परंपरा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंकिमचंद्र चटर्जी की लेखनी से निकला 'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता और राष्ट्रप्रेम की चेतना का उद्घोष बना, तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का 'जन गण मन' भारत की विविधता में एकता और सामूहिक राष्ट्रीय भावना का स्वर बना। इन रचनाओं ने सिद्ध किया कि साहित्य केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की चेतना को दिशा देने वाली शक्ति भी है।

इसी विराट परंपरा में हिंदी ने जनमानस के प्रेम, पीड़ा, संघर्ष, भक्ति और स्वाभिमान को अपनी आवाज दी। हिंदी की यात्रा को कुछ नामों तक सीमित करना संभव नहीं, लेकिन कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, हरिवंश राय बच्चन और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' जैसे रचनाकारों ने अपने-अपने समय को हिंदी में बोलना सिखाया।

कबीर ने निर्भीक वाणी से सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। तुलसीदास ने लोकभाषा में भारतीय जीवन और आस्था को व्यापक जनमानस से जोड़ा। बच्चन ने आधुनिक मनुष्य की संवेदनाओं को शब्द दिए और दिनकर ने हिंदी कविता में ऐसा ओज भरा, जिसमें राष्ट्र का स्वाभिमान,

संघर्ष और चेतना एक साथ दिखाई देती है।

समय बदला तो हिंदी के सामने चुनौतियां भी बदलीं। आज तकनीक, इंटरनेट और बदलती जीवनशैली के दौर में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हिंदी अपनी जड़ों से जुड़ी रहते हुए नई पीढ़ी से संवाद कैसे करे। इसी संदर्भ में आधुनिक हिंदी कविता के लोकप्रिय स्वर डॉ. कुमार विश्वास का योगदान महत्वपूर्ण दिखाई देता है।

कुमार विश्वास ने कविता को केवल पुस्तकों और साहित्यिक मंचों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी प्रभावी वाणी और मंचीय प्रस्तुति के माध्यम से कविता को सामान्य श्रोता, खासकर युवाओं के करीब पहुंचाया। उनकी कविताओं में प्रेम, विरह, जीवन के अनुभव, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र के प्रति आत्मीय भाव दिखाई देते हैं।

उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने कविता को केवल सुनने की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे महसूस करने का अवसर दिया। साहित्य से दूर व्यक्ति भी जब उनकी प्रस्तुति में अपने जीवन, भावनाओं और अनुभवों की झलक पाता है, तो हिंदी उसके लिए केवल भाषा या पाठ्यक्रम का विषय नहीं रहती, बल्कि अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है।

यहीं दिनकर और कुमार विश्वास के बीच हिंदी की निरंतरता दिखाई देती है। दिनकर की हुंकार ने अपने समय में राष्ट्र के स्वाभिमान और संघर्ष को स्वर दिया, जबकि कुमार विश्वास की वाणी ने आधुनिक समय में कविता को नई पीढ़ी के अनुभवों और भावनाओं से जोड़ा। यह तुलना किसी को बड़ा या छोटा साबित करने के लिए नहीं, बल्कि यह समझने के लिए है कि हर युग हिंदी को उसकी आवश्यकता के अनुरूप नया स्वर देता रहा है।

हिंदी दिवस केवल हिंदी की प्रशंसा करने का दिन नहीं, बल्कि उसके प्रति अपने दायित्व को समझने का अवसर भी है। भाषा का सम्मान केवल आयोजनों और नारों से नहीं होता। उसका वास्तविक सम्मान तब है, जब वह ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, साहित्य और संवाद की स्वाभाविक भाषा बने।

हिंदी को भविष्य की भाषा बनाने के लिए उसके गौरवशाली अतीत पर गर्व के साथ उसे नए समय के अनुरूप समृद्ध करना होगा। नई पीढ़ी के सपनों, तकनीक और बदलती दुनिया से हिंदी का संवाद जितना मजबूत होगा, उसका भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा।

आज हिंदी दिवस पर हमें बंकिमचंद्र चटर्जी के राष्ट्रप्रेम, टैगोर की राष्ट्रीय चेतना, कबीर की निर्भीकता, तुलसी की आत्मीयता, बच्चन की संवेदना, दिनकर के स्वाभिमान और कुमार विश्वास की संवादशील वाणी से प्रेरणा लेने की जरूरत है।

क्योंकि विरासत हमें अतीत से मिलती है, लेकिन उसका भविष्य हमारे दायित्व से बनता है।

हिंदी की यात्रा अनवरत है। समय बदलेगा, मंच बदलेंगे और पीढ़ियां भी बदलेंगी, लेकिन जब तक शब्दों में अपनी मिट्टी की सुगंध और हृदय में अपनी भाषा के प्रति सम्मान जीवित रहेगा, हिंदी केवल बोली नहीं जाएगी-वह महसूस की जाएगी, जी जाएगी और पीढ़ियों तक अपना मान बढ़ाती रहेगी।

टैक्स वसूलने वाली सरकार खुद अँधेरे में !

25 लाख के फेर में काटी बिजली

• चंचल द्विवेदी, संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बेहद चौंकाने वाली प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है, शहर भर से करोड़ों का संपत्ति कर और यूजर चार्ज वसूलने वाले रायपुर नगर निगम ज़ोन-10 की बिजली काट दी गई, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि निगम पर लगभग 25 लाख का बिजली बिल लंबे समय से बकाया था, बिजली गुल होते ही निगम में पूरी तरह 'ब्लैकआउट' छा गया। दफ्तर के कंप्यूटर्स, सर्वर, डेटा एंट्री सिस्टम और ऑनलाइन फाइल प्रोसेसिंग का काम पूरी तरह ठप्प हो गया। उमस और गर्मी के बीच दूर-दूर से अपनी समस्याओं को लेकर आए आम नागरिकों को घंटों बिना काम कराए भटकना पड़ा। अधिकारियों के कमरों के एसी और पंखे बंद होने से पूरे दफ्तर में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

बिजली विभाग (CSPDCL) के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नगर निगम को पिछले कई महीनों से बार-बार नोटिस जारी कर बकाया 25 लाख का भुगतान करने की चेतावनी दी जा रही थी। बिला भुगतान के प्रति निगम प्रशासन का रवैया ढीला ढाला रहा, जिसके बाद नियमों के तहत 'पावर सप्लाई स्विच ऑफ' करने की सख्त कार्रवाई की गई, दरअसल, पूरे प्रदेश में जून 2026 तक सरकारी विभागों पर 3,035 करोड़ से अधिक का बिजली बिल बकाया है, जिसमें सबसे बड़ा डिफॉल्टर नगरीय प्रशासन विभाग ही है, इसके मद्देनजर सरकार ने 1अगस्त 2026 से सभी बड़े सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम शुरू की है दफ्तर की बत्ती गुल होने और मीडिया में खबर फैलते ही नगर निगम के प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में निगम के वित्तीय अधिकारियों ने बजट का रोना रोते हुए बिजली कंपनी के आला अफसरों से बात की। निगम द्वारा फंड रिलीज करने के आश्वासन और तत्काल एक हिस्से का भुगतान करने की कागजी प्रक्रिया शुरू होने के बाद बिजली विभाग ने अस्थायी रूप से सरकारी दफ्तर की बिजली बहाल कर दी, ताकि सरकारी काम और आम जनता प्रभावित न हो। लेकिन इस घटना ने निगम के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। इस पूरी कार्रवाई ने बिजली कंपनी के उस दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है, जिससे रायपुर की आम जनता हर दिन जूझती है। रायपुर के उपभोक्ताओं का

CSPDCL
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

कहना है कि यदि किसी आम नागरिक का बिल महज 2,000 भी बकाया हो या भुगतान में 10 दिन की भी देरी हो जाए, तो CSPDCL के कर्मचारी बिना कोई मोहलत दिए घर का कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। वर्तमान में रायपुर की जनता महंगे बिजली बिलों और स्मार्ट मीटर के कारण पहले ही आक्रोशित है, आम घरों का बिल जहां 400 रुपये से बढ़कर सीधे हजारों में आ रहा है, वहीं बिजली कटौती के कारण लोगों को रातों में जागना पड़ रहा है जनता का सीधा सवाल है कि जब आम आदमी पर पेनाल्टी और तुरंत कनेक्शन काटने का चाबुक चलाया जाता है, तो लाखों का बिल दबाकर बैठे सरकारी बाबुओं और नगर निगम को महीनों की मोहलत क्यों दी जाती है? क्या नियम सिर्फ गरीबों के लिए हैं?

अब आगे देखने का विषय होगा की 25 लाख के बकाया का भुगतान कब होता है

Gen-Z के बाद Gen-Alpha क्यों उतरी सड़को पर ?

•चंचल द्विवेदी, संवाददाता, रायपुर

इन दिनों स्कूल के बच्चे भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कहीं शिक्षक नहीं हैं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं स्कूल भवन जर्जर हैं, तो कहीं हॉस्टल में बिजली और खाने की समस्या बच्चों को परेशान कर रही है।

सवाल है - क्या ये समस्याएं अचानक पैदा हुई हैं? शायद नहीं। इनमें से ज्यादातर समस्याएं पुरानी हैं। नया अगर कुछ है, तो वह है बच्चों का अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर आवाज उठाना।

Gen Z के दौर में NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों के बड़े विरोध प्रदर्शन ने यह दिखाया कि युवा अपनी मांगों के लिए संगठित होकर सिस्टम से जवाब मांग सकते हैं। अब इसी बदलाव की झलक Gen Alpha यानी आज की स्कूली पीढ़ी में भी दिखाई दे रही है।

इसका ताजा उदाहरण शिवपुर एकलव्य विद्यालय, सरगुजा है। 7 सितंबर 2026 को शिवपुर (बतौली) से 45 से ज्यादा छात्राएं करीब 30 किलोमीटर पैदल चलकर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। हॉस्टल में 3 महीने से बिजली नहीं होने और शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राओं के इस कदम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले का संज्ञान लिया।

वहीं पेंड्रावन आत्मानंद स्कूल, दुर्ग में बच्चों ने शिक्षकों की कमी को लेकर दो बार चक्काजाम किया। 21 अगस्त 2026 को धमधा-खैरागढ़ हाईवे करीब 4 घंटे जाम रहा।

इसके बाद 25 अगस्त 2026 को दोबारा प्रदर्शन हुआ, जो करीब 12 घंटे चला। करीब 400 विद्यार्थियों की मांग शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था थी।

25 अगस्त 2026 को ही सेलूद आत्मानंद स्कूल, दुर्ग के करीब 200 बच्चों ने पिछले 2 साल से टॉयलेट नहीं होने के विरोध में दुर्ग-पाटन मुख्य मार्ग के बजरंग चौक पर चक्काजाम किया।

छुरी एकलव्य स्कूल, कोरबा में अगस्त 2026 में बच्चों ने एक ही महीने में तीन बार प्रदर्शन किया। 13 अगस्त 2026 को सुबह 6:45 बजे से करीब 5 घंटे तक कोरबा-कटघोरा हाईवे जाम रखा गया, जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिला।

इसी तरह लैलूंगा एकलव्य स्कूल, रायगढ़ में अगस्त के मध्य में खराब खाने और प्रिंसिपल की मनमानी के खिलाफ बच्चों ने पढ़ाई का बहिष्कार किया। मूरकौल और बलरामपुर के अन्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर बच्चे हड़ताल कर DEO कार्यालय तक पहुंचे। वहीं हीरापुर हायर सेकेंडरी स्कूल, माकड़ी, कोंडागांव में छात्रों ने शिक्षकों के व्यवहार और अपनी मांगों को लेकर सड़क जाम कर करीब 1 घंटे तक नारेबाजी की।

इन घटनाओं को सिर्फ अलग-अलग विरोध प्रदर्शन मानना आसान है, लेकिन तस्वीर इससे बड़ी है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए करीब 22 हजार 466 करोड़ रुपये का बजट रखा है। लेकिन सवाल बजट का सिर्फ आकार नहीं है। सवाल है-उस बजट का असर स्कूल की जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर बच्चों को सड़क पर उतरना पड़े... प्रदर्शन करना पड़े... तो फिर बजट और व्यवस्था के बीच कहीं न कहीं गैप जरूर है।

सरकार द्वारा कुछ जगहों पर कार्रवाई की गई और समाधान भी दिए गए, लेकिन यह एक गंभीर सवाल है कि क्या बच्चों को अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या बिना प्रदर्शन किए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है? आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब खुद पहल करके व्यवस्था सुधारेंगे, ताकि किसी भी बच्चे को न्याय या सुविधाओं के लिए आंदोलन का रास्ता न चुनना पड़े?

छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स साध्य PSC एकैडमी

प्रश्न 1: छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है?

(A) न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद (B) शत्रुघ्न सिंह

(C) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (D) मोहन पवार

सही उत्तर: (C) न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति की पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस विशेषज्ञ समिति में शत्रुघ्न सिंह, एम. के. राऊ, मोहन पवार और ज्योति रानी सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया है।

प्रश्न 2: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम में चयनित होकर रजत पदक जीतने वाली ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है?

(A) बिलासपुर (B) दुर्ग

(C) रायपुर (D) राजनांदगांव

सही उत्तर: (D) राजनांदगांव

व्याख्या: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की अंतरराष्ट्रीय महिला वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने महिला 53 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम (स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम) वजन उठाकर रजत पदक (सिल्वर मेडल) हासिल किया और स्नैच राउंड में 88 किलोग्राम भार उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया।

प्रश्न 3: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की पहली 'खुली जेल' (Open Jail) को ₹23 करोड़ की लागत से किस जिले के 'पथरा' गांव में शुरू करने की मंजूरी दी है?

(A) बेमतरा (B) दंतेवाड़ा

(C) महासमुंद (D) सरगुजा

सही उत्तर: (A) बेमतरा

व्याख्या: राज्य सरकार ने बेमतरा जिले के पथरा गांव में छत्तीसगढ़ की पहली खुली जेल (ओपन जेल) विकसित करने का आदेश जारी किया है। इसके शुरुआती चरण में जेल में अच्छे आचरण वाले 200 आजीवन कारावास के कैदियों को रखा जाएगा, जहाँ उन्हें अपने परिवार के साथ रहने तथा कृषि व पशुपालन के माध्यम से समाज में पुनर्वास के अवसर दिए जाएंगे।video

प्रश्न 4: हाल ही में जून 2026 में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई जी का निधन हो गया। उन्हें भारत सरकार द्वारा किस वर्ष देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था?

(A) 1988 (B) 2003

(c) 2019 (D) 1995

सही उत्तर: (C) 2019

व्याख्या: छत्तीसगढ़ की महान पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई जी का 5 जून 2026 को एम्स में निधन हो गया। उन्हें लोक संस्कृति में उनके अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण और वर्ष 2019 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से अलंकृत किया गया था।

प्रश्न 5: 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हुए 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026' के तहत किसी नाबालिग, महिला या सामूहिक रूप से जबरन मंतारण (धर्म परिवर्तन) कराने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है?

(A) 7 से 10 साल की जेल (B) आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 25 लाख रुपये का जुर्माना

(C) 5 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना

(D) 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना

सही उत्तर: (B) आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 25 लाख रुपये का जुर्माना

व्याख्या: पुराने 1968 के कानून की जगह 10 जुलाई 2026 से नया 'छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026' प्रभावी हो गया है। इसके तहत पैसे के लालच या धोखे से मंतारण करने पर 7 से 10 साल की जेल का प्रावधान है, लेकिन यदि मंतारण किसी नाबालिग, महिला का हो या सामूहिक रूप से किया गया हो, तो आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये के भारी जुर्माने की कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

प्रश्न 6: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में छत्तीसगढ़ की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के तहत 'रजत कमल पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है? (A) जोगीमारा (B) अबूझमाड़

(C) रामनामी (D) महानदी

सही उत्तर: (C) रामनामी

व्याख्या: भारत बाला गणपति द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म "रामनामी" को 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री श्रेणी के अंतर्गत 'रजत कमल पुरस्कार' प्रदान किया गया है। यह फिल्म जांजगीर-चांपा क्षेत्र में मुख्य रूप से संकेंद्रित रामनामी समुदाय की अनूठी संस्कृति और उनके पूरे शरीर पर राम-राम गोदवाने की अटूट आस्था को दर्शाती है।

प्रश्न 7: वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) समाप्त होने के बाद, देश के किस पूर्व सुरक्षा कैंप को स्थानीय समुदाय की सेवा के लिए 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र' (प्रथम जन सुविधा केंद्र) के रूप में स्थापित किया गया है?

(A) गीदम कैंप (दंतेवाड़ा) (B) कुनकुरी कैंप (जशपुर)

(C) गरियाबंद कैंप (D) नेतानार कैंप, जगदलपुर (बस्तर)

सही उत्तर: (D) नेतानार कैंप, जगदलपुर (बस्तर)

व्याख्या: मार्च-अप्रैल 2026 तक छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या घटकर शून्य होने के बाद खाली हुए कैंपों को जन सुविधा केंद्रों में बदला जा रहा है। इसी पहल के तहत बस्तर के जगदलपुर में स्थित 'नेतानार कैंप' देश का पहला ऐसा सुरक्षा कैंप बना है, जिसे 'शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा केंद्र' नामक जन सुविधा केंद्र के रूप में स्थानीय समुदाय के लिए समर्पित किया गया है।

प्रश्न 8: छत्तीसगढ़ के किस जिले के 'ग्राम बाबा मोहतरा' के तालाब में ग्रामीणों के साथ करीब 175 वर्षों तक रहने वाले मगरमच्छ 'गंगाराम' की कहानी को एनसीईआरटी (NCERT) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा?

(A) बेमतरा (B) नारायणपुर

(C) गरियाबंद (D) जसपुर

सही उत्तर: (A) बेमतरा

व्याख्या: बेमतरा जिले के ग्राम बाबा मोहतरा के एक तालाब में रहने वाले मगरमच्छ 'गंगाराम' और ग्रामीणों के बीच इंसान व वन्यजीव के अनूठे रिश्ते की कहानी को एनसीईआरटी (NCERT) के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2019 में इस मगरमच्छ की मृत्यु होने पर पूरे गांव ने शोक मनाया था तथा रीति-रिवाजों के साथ अंतिम विदाई देकर तालाब के पास उसकी एक भव्य प्रतिमा और स्मारक भी बनवाया है।

प्रश्न 9: छत्तीसगढ़ राज्य की पहली 'राजकीय तितली' का चुनाव करने के लिए वन विभाग की विशेषज्ञ समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट की गई तीन प्रजातियों की दौड़ में कौन सी तितली प्रजाति शामिल नहीं है?

(A) कॉमन बैंडेड पीकॉक (Common Banded Peacock) (B) स्पॉट टेल (Spot Tail)

(C) ऑरेंज ओकलीफ (Orange Oakleaf) (D) ब्लू मॉर्मन (Blue Mormon)

सही उत्तर: (D) ब्लू मॉर्मन (Blue Mormon)

व्याख्या: छत्तीसगढ़ सरकार तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 'राजकीय तितली' का चयन करने जा रही है। इसके लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने तीन प्रजातियों-कॉमन बैंडेड पीकॉक, स्पॉट टेल, और ऑरेंज ओकलीफ को शॉर्टलिस्ट (दौड़ में शामिल) किया है, जबकि ब्लू मॉर्मन इसमें शामिल नहीं है।

प्रश्न 10: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर (अबूझमाड़) जिले के किन स्थानीय एवं पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया हाल ही में शुरू की गई है?

(A) पीला कोसरा, काला कोसरा और तीखुर (B) जस्पोर और जसक्राफ्ट

(C) हंसुली और गिलर आभूषण (D) कोसा सिल्क और वन कंद

सही उत्तर: (A) पीला कोसरा, काला कोसरा और तीखुर

व्याख्या: नारायणपुर (अबूझमाड़) के तीन प्रमुख उत्पादों—'पीला कोसरा' (आर्क जो औषधीय गुणों से भरपूर और डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है), 'काला कोसरा' (गहरे छिलके वाला कुटकी मिलेट) और 'तीखुर' (हल्दी परिवार का कंद) को जीआई टैग (GI Tag) दिलाने की प्रक्रिया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के प्रयासों से शुरू की गई है।

विधानसभा में कुछ विधायकों की उपस्थिति नगण्य कई विधायकों का अटेंडेंस शत-प्रतिशत

सबसे ज्यादा उपस्थिति वाले विधायक | **सबसे कम उपस्थिति वाले विधायक**

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधानसभा को शुरू हुए ढाई साल बीत चुके हैं। इस दौरान आहूत किए गए अलग-अलग सत्रों में विधायकों की उपस्थिति का जो आंकड़ा सामने आया है, वह लोकतंत्र के प्रति उनकी गंभीरता की पोल खोलता है। 19 दिसंबर 2023 से 17 जुलाई 2026 तक चले विधानसभा सत्रों में कुछ विधायकों ने अपनी शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कर मिसाल पेश की है, तो वहीं कुछ विधायकों ने सदन से ऐसी दूरी बनाई है जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

विधायक सदन में अपने क्षेत्र के सवाल पूछते हैं या नहीं, अगर इस प्रश्न को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया जाए, तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है कि बहुत से विधायक सदन में उपस्थित ही नहीं होते। किसी विधायक को मेडिकल इमरजेंसी या कोई आवश्यक काम हो सकता है, यह बात समझी जा सकती है। लेकिन साल में लगने वाले तीन अलग-अलग महत्वपूर्ण सत्रों-बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र- में लगातार इतनी कम उपस्थिति रहना कोई संयोग नहीं कहा जा सकता। यह कैसे संभव है कि उसी समय उन्हें विधानसभा सत्र से भी अधिक अति आवश्यक काम रहता होगा या लगातार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता होगा? इसे महज एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह जनता द्वारा सौंपे गए दायित्वों के प्रति सीधे तौर पर लापरवाही है।

सदन में जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी निभाने वाले विधायकों में शकुंतला सिंह पोर्ते, प्रेमचन्द पटेल, अनुज शर्मा, रोहित साहू, रिकेश सेन और डोमनलाल कोर्सेवाडा ने पूरे 79 दिन उपस्थित रहकर बेहतरीन काम किया है।

दूसरी ओर, रेणुका सिंह सरुता, कवासी लखमा, राजेश मूणत, देवेन्द्र यादव और सुनील सोनी जैसे विधायक हैं जिनकी उपस्थिति सबसे निचले पायदान पर है। हांलाकि ये बात अलग है कि विधायक कवासी लखना और देवेंद्र यादव कुछ समय जेल में भी रहे हैं और सुनील सोनी उपचुनाव जीतकर बाद में आए हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो उन विधायकों पर उठता है जो दिखाई नहीं दिए। जब विधायक सदन में रहेंगे ही नहीं, तो अपने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा कैसे करेंगे? जनता इन्हें चुनकर इसलिए भेजती है ताकि वे विधानसभा में उनके हक की बात करें, न कि सदन की कार्यवाही से नदारद रहें। सदन में उनकी यह अनुपस्थिति उनके वादों और जनता के प्रति उनकी जवाबदेही पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है।

विधायकों की उपस्थिति

सबसे ज्यादा और सबसे कम उपस्थिति वाले विधायक

सबसे ज्यादा उपस्थिति वाले विधायक

उपस्थिति	विधायकों के नाम
79 दिन (कुल 6 विधायक)	शकुंतला सिंह पोर्ते, प्रेमचन्द पटेल, अनुज शर्मा, रोहित साहू, रिकेश सेन, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा
78 दिन (कुल 5 विधायक)	उद्देश्वरी पैकरा, गोमती साय, पुन्नूलाल मोंहले, इन्द्र कुमार साहू, भावना बोहरा
77 दिन (कुल 6 विधायक)	चातुरी नंद, मोतीलाल साहू, पुरन्दर मिश्रा, अंबिका मरकाम, ललित चंद्राकर, यशोदा निलाम्बर वर्मा
76 दिन (कुल 9 विधायक)	रायमुनी भगत, धर्मजीत सिंह, धरम लाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, संगीता सिन्हा, ईश्वर साहू, भोलाराम साहू, नीलकंठ टेकाम, बघेल लखेश्वर

सबसे कम उपस्थिति वाले विधायक

क्रम	विधायक	उपस्थिति
1	रेणुका सिंह सरुता	32 दिन
2	कवासी लखमा	45 दिन
3	राजेश मूणत	50 दिन
4	देवेंद्र यादव	50 दिन
5	सुनील सोनी	52 दिन

तीजा-पोरा तिहार में रंगिस पूरा छत्तीसगढ़ !

तीजा मिलान में उमड़िस बहिनी मन के सैलाब, नेता मन संग मनाइस तिहार

• **आरती बेनिया,** संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के सियासत अउ संस्कृति के अटूट रिस्ता एक बार फेर ले तीजा अउ पोरा तिहार में दिखाई दिस। सत्ता पक्ष होय या विपक्ष, जम्मो नेता मन अपन-अपन ढंग ले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार ला मनईस, कहुं मइके कस लइका मन बर खुरमी-ठेठरी बनिस, त कही पारंपरिक सुआ-कर्मा नाच, सावन के झूला अउ ठेठरी-खुर्मी के खुशबू महकत राहय, उंही तीजा के मंच ले महंगाई ऊपर करारा तंज घलो कसे गिस। आवव देखथन ए दारी के तीजा-पोरा तिहार कइसे खास रहिस ?

नवा रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में तीजा-पोरा तिहार अब्बड़ धूमधाम से मनाए गीस। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेवता में प्रदेश भर से हजारों माईलोगन, तिजहारिन बहिन मन सीएम हाउस पहुंचिन। पूरा मुख्यमंत्री निवास ह बहिन मन बर मायके कस सजे राहय। चारों कोती छत्तीसगढ़ी संस्कृति के रंग, सुग्घर पारंपरिक सुआ-कर्मा नाच, सावन के झूला अउ ठेठरी-खुर्मी के खुशबू महकत राहय। मुख्यमंत्री ह भगवान शिव-पार्वती अउ माटी के नंदिया बैल के पूजा-अर्चना करिन।

कुपोसण भगाए बर 'हर घर मुनगा' अभियान

महिला अउ बाल विकास विभाग डहर ले रखे गए ए राज-स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ह लइका मन अउ महतारी मन के सुघर सेहत बर एक बड़का घोसणा करिन। सीएम साय ह 'हर घर मुनगा' अभियान के सुरुवात करिन। ओमन कहिन कि कुपोसण अउ एनीमिया ला दूर करे बर घर-घर मुनगा के पौधा बांटे जाही, काबर कि मुनगा में आयरन अउ कैल्शियम के भंडार रथे, जेकर ले लइका मन अउ नोनी-बाबू मन ल भरपूर पोसण मिलही।

बड़-बड़ नेता अउ बहिन मन शामिल हुईं

ए सुग्घर तिहार में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, महिला अउ बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर के महापौर मीनल चौबे समेत अब्बड़ अकन बहिन मन अउ लइका मन शामिल हुईं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के धरमपत्नी वीणा सिंह अउ उनकर बहू घलो ए कार्यक्रम में पहुंच के तिहार के आनंद उठाइन। ए आयोजन ह हमर छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा, सुपोषण अउ मया-दुलार के एक बड़े मिसाल बन गीस।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास में मइके कस जुटिस भीड़, महंगाई ऊपर बरसिन बघेल

रायपुर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में तीजा-पोरा के तिहार अब्बड़ धूमधाम ले मनाय गिस। निवास ला पूरा पारंपरिक रूप ले तोरई अउ फूल मन ले सजाय गे रहिस, जउन ह बहिन मन बर मइके कस लगिस। कार्यक्रम में नामी गायिका मन तीजा के पारंपरिक गीत गाके समां बांध दिन, जेमा छत्तीसगढ़ के जम्मो बहिन मन जमके थिरकिन अउ आनंद लीन।

ये दौरान मंच ले महंगाई ऊपर पूर्व सीएम ह तंज घलो कसीन हे, तिहार के आनंद के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ह मंच ले जनता के दुख-पीरा ला उठावत सत्ता पक्ष ऊपर जमके हमला बोलिन। ओमन कहिन कि शक्कर अउ पेट्रोल अत्तक महंगा होगे हे कि अब गाड़ी में पेट्रोल के जगह गन्ना डालके चलाय के दिन आ गे हे। बिजली बिल के बाढत कीमत ऊपर तंज कसत ओमन कहिन कि आम जनता बिजली बिल पटा-पटा के थक चुके हे।

मंत्री रामविचार नेताम के बंगले में पत्नी ह अपन हाथ ले बनाइस ठेठरी-खुरमी, करीन बैलगाड़ी के सवारी

सत्ता पक्ष भाजपा कोति ले प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास में छत्तीसगढ़िया संस्कृति के परछाई साफ दिखीस। तिहार के दिन मंत्री जी के धर्मपत्नी ह अपन हाथ ले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवान ठेठरी, खुरमी, चौसेला अउ उड़द दाल के बरा तइयार करिन। नेताम परिवार ह माटी के बइला अउ जाता-पोरा के विधि-विधान ले पूजा-अर्चना करिस। एकर बाद मंत्री रामविचार नेताम ह पारंपरिक छत्तीसगढ़िया टोपी पहिनके अपन पत्नी ला संग बइठाके बैलगाड़ी में सवारी करिन, जउन ह सोशल मीडिया में अब्बड़ पसंद करे जावत हे।

भंगाराम माई जातरा: बस्तर के अनूठा परंपरा जिहां देवी-देवता मन ला दे जाथे सजा

• **शशिकला साहू,** संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के कोंडागांव जिला के केशकाल इलाका म सुरडोंगर के पहाड़ी हे। इहां हर बछर एक अइसन धमर-करम के परंपरा निभाये जाथे, जउन ला सुन के देस अउ दुनिया के मनखे मन अचरज म पर जाथे। ए आय हमर भंगाराम माई जातरा। ए परंपरा हमर आस्था के बड़े केन्द्र आय। ए जातरा म सिरिफ देवी-देवता मन के पूजा नइ होए, बल्कि उंकर अदालत घलो लगथे। मनखे मन के अइसन मानना हे कि ए दरबार म उही देवी-देवता मन के पेसी होथे, जेकर ले जुरे गांव के मनखे मन अपन दुख-दरद अउ सिकायत ला लेके माई के दरबार म आथे।

भंगाराम माई के मंदिर बस्तर के आदिवासी संसकिरिती,आस्था अउ परंपरा के सबले बड़े जगा आय। हर बछर होए वाला ए जातरा म कोंडागांव जिला के संगे-संग पूरा बस्तर अंचल अउ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जगा ले हजारो के भीड़ म भगत मन आथे। एला छोड़ के परोसी राज मध्यप्रदेश अउ ओड़िसा ले घलो मनखे मन ए एतिहासिक आयोजन म संघरे बर आथे। ए बेरा म देवी-देवता मन के चीन्हा, आंगा देव, सिरहा, गुनिया, मांझी अउ गायता के संग गांव वाला मन अपन पारंपरिक भेस म संघरथे।

भादो महिना म होथे भंगाराम माई जातरा

भंगाराम माई जातरा हर बछर भादो महिना म मनाये जाथे। इहां के मनखे मन के मानना हे कि भादो महिना के पहिली सनिच्चर ले मंदिर म बिसेस पूजा-पाठ सुरु हो जाथे, जउन ह आखरी सनिच्चर तक चलथे। इही आखरी सनिच्चर के दिन मुख्य जातरा के आयोजन होथे। इही दिन ला देवता मन के पेसी अउ अदालत लगे के दिन माने जाथे। सासन-परसासन डहर ले इहां बढ़िया बेबस्था करे जाथे, ताकि कोनो भगत ला कोनो परेसानी झन होवय।

दूरिहा-दूरिहा के गांव ले मनखे मन अपन-अपन गांव के देवता मन के चीन्हा ला धर के भंगाराम माई के दरबार म पहुंचथे। बाजा-गाजा, ढोल-नगाड़ा अउ पुरखा मन के रिति-रिवाज के संग देवी-देवता मन के जातरा निकाले जाथे। मंदिर म पहुंचे के बाद सब देवता मन के आघू म बिसेस पूजा अउ सुनवाई के काम सुरु होथे।

देवता मन के अदालत काबर लगथे?

बस्तर के आदिवासी समाज म हर गांव के अपन अलग-अलग देवी-देवता होथे। ए देवता मन ला गांव के रकच्छा करे, बीमारी ला दूरिहा भगाये, फसल ल बचाये, अउ गांव म सुख-सांती बनाये राखे के जिम्मेदारी दे जाथे। गांव वाला मन के मानना हे कि अगर कोनो देवता अपन काम ला बने तरीका ले नइ करय,पूजा-पाठ करे के बाद घलो गांव म सरलग परसानी बने रहिथे,या मनखे मन के मुराद पूरा नइ होवय, त ओकर सिकायत भंगाराम माई के दरबार म करे जाथे।

इही बिसवास के आधार म भंगाराम माई के मंदिर म बछर म एक घाव देवता मन के अदालत लगथे। एला बस्तर के समाजिक अउ धरम के नियाय बेबस्था के चीन्हा माने जाथे।

कइसे होथे देवता मन के पेसी?

देवता मन के अदालत म गांव के मनखे मन अपन गांव के देवता के चीन्हा जइसे आंगा देव, डोली, छतर या दूसर चीन्हा ला लेके माई के दरबार म आथे। जउन देवता के सिकायत होथे, ओकर परतिनिधि के रूप म सिरहा (पुजारी) घलो उहां हाजिर रथे। आदिवासी मानता के अनुसार देवता के सक्ती ओकर सिरहा म आथे अउ उही सिरहा के जरिये देवता ह अपन बात ला राखथे।

बस्तर के आदिवासी इलाका म हर गांव म अब्बड़ अकन देवता माने जाथे, ओमन ला अलग-अलग चीन्हा या मूरति के रूप म पूजे जाथे। देवता मन के काम घलो बंटे हवय। कोनो बीमारी ला दूरिहा करथे त कोनो फसल के रकच्छा करथे। जउन देवता अपन भगत मन के आस ला पूरा नइ करय या ओमन ला परसान करथे, त उंकर सिकायत भंगाराम माई ले करे जाथे।

भंगाराम माई के सिरहा (परधान पुजारी) ए पूरा काम ला करथे। गांव वाला अपन समस्या अउ सिकायत ला बताथे। ओकर बाद देवता के सिरहा ले पुछताछ होथे अउ परंपरा के अनुसार नियाव सुनाय जाथे।

देवता मन ला काबर दे जाथे सजा?

आदिवासी समाज म देवी-देवता मन ला घलो जिम्मेदारी के संग जुरे माने जाथे। मानता हे के जउन देवता ला गांव के रकच्छा करे के काम दे गे हे, अगर वोहा अपन भगत मन के रकच्छा नइ कर पावय त ओला घलो जवाब दे ला परथे। अगर सुनवाई के बाद कोनो देवता ला दोसी पाय जाथे, त ओला सजा दे जाथे। ए सजा भंगाराम माई के आदेस माने जाथे।

कइसे दे जाथे देवता मन ला सजा?

दोसी पाये गे देवता मन के चीन्हा ला भंगाराम माई मंदिर के तीर म एक तय जगा म छोड़ दे जाथे। ए जगा ला देवता मन के आराम करे के जगा या देवता मन के जेल घलो कहे जाथे। इहां देवता के चीन्हा ला एक बछर तक रखे जाथे।

बछर भर तक गांव म परसान करइया अइसन देवी-देवता या बाहरी सक्ती मन ला भेंट चढ़ा के गांव के देवी सीतला माई के पूजा करे जाथे। परसान करे वाला देव के नाव म सकलाय गे समान ला टुकना म रख के गांव ले बाहिर रख दे जाथे।

इहां के मनखे मन के मानना हे कि जउन जगा म सजा पाय देवता मन के चीन्हा ला रखे जाथे, उहां रखे समान के कोनो चोरी नइ करय। इहां तक के अगर उहां सोना-चांदी के गहिना या दूसर कीमती समान घलो रखे राहय, त वोहा बांचे रहिथे। गांव वाला मन एला भंगाराम माई के सक्ती अउ नियाय के परमान मानथे।

एक बछर बाद होथे देवता मन के बिदई

सजा पूरा होय के बाद, अवइया जातरा म ए देवी-देवता मन के बिधि-बिधान ले बिदई करे जाथे। बिहनिया ले सुरु होए वाला ए काम संझा तक चलथे। एकर बाद गांव वाला मन अपन-अपन देवता ला फेर अपन गांव लेके जाथे।

भंगाराम माई के सबले बड़े मानता ए हे कि उंकर आदेस के बिना ए पूरा अंचल म कोनो नवा देवता के इसथापना या पूजा सुरु नइ करे जावय। माई ला सबो देवी-देवता मन के मुखिया के रूप म माने जाथे। ए जातरा हमर बस्तर अउ छत्तीसगढ़ के वो सुग्घर परंपरा आय, जउन ला दुनिया भर म जाने अउ माने जाथे। ए सिरिफ एक पूजा नइ, भल्कू नियाय अउ बिसवास के एक अइसन अटूट बंधन आय, जउन मनखे अउ देवता दुनो ला जिम्मेदारी के पाठ पढ़ाथे।